(ख) यह योजना कब ग्रारम्भ की जायेगी ग्रौर इसमें कितना खर्चा ग्रायेगा ग्रौर प्रतिवर्ष कितने भूतपूर्व सैनिकों को यह प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) ग्रौर (ख)ः सरकार ने सेना कार्मिकों के लिए, उनकी सेवा के म्रन्तिम वर्ष में ''सेवा कालीन प्रशिक्षण'' की एक विशेष योजना मंजूर कर ली है ताकि वे सिविल क्षेत्र में नौकरियां पा सकें। इस योजना में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी उद्यमों में चुने हुए 10 ट्रेडों में जो राष्ट्रीय ज्यावसायिक ट्रेड प्रशिक्षण परिषद् द्वारा म्रनुमोदित है, 9 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा । भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धा-रित न्यूनतम ग्रारक्षण के ग्रनुसार इन उप-कमों को सेना कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए म्रनिवार्यतः लेना होगा । म्रारम्भ में हर साल 2,000 सेना कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है। यह योजना मार्च, 1981 तक शुरू हो जाएगी। इस पर 2.08 लाख रुपये सालाना खर्च होने का ग्रनुमान है । योजना चालू होने के बाद प्राप्त होने वाले <del>ग्रनुभव के</del> म्राधार पर योजना का म्रौर विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि हर वर्ष 4,000 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा सके । फिलहाल 10,000 कार्मिकों को प्रशिक्षणं देने का लक्ष्य रखा गया है ।

## Leh-Manali Road

1239. SHRI P. NAMGYAL: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) when the Leh-Manali Road between Ladakh in J&K and Himacha] Pradesh will be completed;

(b) whether any proposal is afoot to upgrade the said road and if not, state reasons therefor; and (c) whether there is any proposal to build an all weather highway to keep the Ladakh region linked with rest of the country in view of unfavourable weather conditions at ZOJI-LA and Kashmir valley?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) Construction of the road was completed in 1973.

(b) No, Sir. Recent assessments relating to Defence needs and cost-effectiveness have not favoured further improvements to the road for the present.

(c) No, Sir.

## Illegal Entry of Foreign Ships

1240. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of DEFENCE

be pleased to state:

(a) whether it is a fact that illegal entry of foreign ships into economic zone of Indian territory in the Bay of Bengal for poaching and smuggling of  $good_s i_s$  on the increase; and

(b) if so, what steps have been taken by the Government to control the illegal entry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) and (b). Foreign vessels/ships are reported to be entering into our Exclusive Economic Zone, in the Bay of Bengal, for poaching purposes. The Govt. has created the Coast Guard Organisation to protect our due sovereign rights in our Exclusive Economic Zone. The Navy also helps the coast Guard this regard. The Coast Guard is still in the process of being organised, Various steps are being taken to augment its force level to deal with illegal entry